THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has taken a view that the work relating to the protection of the ridge would be exclusively vested in the DDA which is also butressed by vesting the powers under the Indian Forests Act, 1927 and Forests (Conservation) Act, 1980 in the DDA.

Contribution for partipating States in NCR Plan

1196. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of participating States which have contributed their share to the National Capital Region Finance Corporation; and

(b) by when the plan is likely to take off?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) The Government has not taken any decision regarding the setting up of a National Capital Region Development Finance Corporation and, therefore, the question of contribution by participating States in the proposed Corporation does not arise.

(b) The NCR Planning Board has an approved outlay of Rs. 200 in the VIII Year Plan, in the State Sector which is an increase from Rs. 35 crore in the VII Plan. Thus a considerable step-up of investment is envisaged in the current Plan period, in order to achieve the objectives of the NCR Plan.

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना–II

@1197. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई महानगर में उपनगरीय रेलगाड़ियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए "मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना II" नामक योजना सरकार के पास भेजी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इस परियोजना के संबंध में निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने विश्व बैंक की वित्तीय मदद पाने हेतु बम्बई नगर परिवहन परियोजना–II (बूट पी–II) प्रस्तुत की है। परियोजना में मौजूदा सड़कों में सुधार विस्तार के साथ-साथ अतिरिक्त फ्लाई ओवरों, सड़कों के निर्माण, मौजूदा उपनगरीय रेल सेवाओं में बढ़ोतरी और अतिरिक्त उपनगरीय रेलवे लाइनों का प्रावधान शामिल है। परियोजना की लागत लगभग 2248.88 करोड़ रुपये है, जिसमें उपनगरीय रेलवे में बढ़ोतरी के लिये 1304.88 करोड़ की राशि शामिल है। तथापि, विश्व बैंक ने कहा है कि वे परियोजना के लिये तभी वित्त प्रदान कर सकते हैं जब उसके उपनगरीय रेलवे घटक का वित्त पोषण देशी संसाधनों द्वारा किया जाए। तदनुसार राज्य सरकार से बूट प्रोजक्ट–II की रेलवे परियोजना के वित्त पोषण के लिये एक उपयुक्त वित्त पोषण पैकेज का सुझाव देने के लिये कहा है।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 798, 8–12–1993 से स्थानांतरित।

उपर्युक्त के आलोक में निर्णय लेने के लिये कोई समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित गुजरात की बहुउद्देशीय परियोजनायें

1198. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की कतिपय बहुउद्देशीय परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और 31 अक्तूबर, 1993 तक उनकी क्या स्थिति थी;

(ग) सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दी जायेगी और उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में सौराष्ट्र में जल संसाधनों का सवक्षण

1199. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जल संसाधनों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या नतीजा निकला ; और

(ग) सरकार द्वारा किन-किन जिलों में सर्वेक्षण करवाया गया और इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है अतः जल संसाधनों के विकास के लिए सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, अन्तर्राज्यीय नदियों के लिए जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए जाते हैं जिनमें गुजरात की नदियां भी शामिल हैं। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने गुजरात में भूजल उपलब्धता के सर्वेक्षण किए हैं। सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में राज्य के वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 6639.03 मिलियन घन मीटर आंके गए हैं, जिनका जिलेवार ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं०	जिले का नाम	कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मिलियन घन मीटर)
1	अमरेली	822.69
2	भावनगर	1329.72
3	जामनगर	993.55
4	जूनागढ़	1251.11
5	राजकोट	1361.67
6	सुरेन्द्र नगर	880.29
	कुल :	6639.03